



न्यायालय राजस्व मण्डल मोप्रमुख्यालय ग्वालियर (मोप्र०)
प्रकरण क्रं. /14 निगरानी

R. 750-प्र०

मित्र अधिकारी
दाम अधि. 3-3-14 को
प्रत्येक
चलाई ओफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मोप्र. ग्वालियर

भैयालाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल
अहिरवार आयु- लगभग 50
वर्ष, निवासी-ग्राम सांदनी,
तहसील व जिला छतरपुर
(मोप्र०)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. शिवराज सिंह
2. सरदार सिंह पुत्र श्री जुहार
सिंह ठाकुर निवासी- ग्राम
सांदनी, तहसील व जिला
छतरपुर(मोप्र०)
3. चुनुचा पुत्र छिल्ला अहिरवार
4. महिला जानकीबाई पुत्री
छिल्ला
5. पूरनलाल पुत्र कन्हैया
6. संतु पुत्र दीना अहिरवार
7. सुन्दरलाल पुत्र दीना अहिरवार
समस्त , निवासीगण ग्राम
सांदनी, तहसील व जिला
छतरपुर (मोप्र०)
8. मोप्र०शासन द्वारा कलेक्टर
महोदय छतरपुर।

.....अनावेदकगण

द्वितीय निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 08.01.2014
पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर
प्रेकरण क्र. 263-19-2005-06 निगरानी शिवराज सिंह
व अन्य बनाम भैयालाल जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का
बंटन आदेश निरस्त करते कब्जा हटाने का आदेश पारित
किया गया, को अपास्त कराने बावत्।

B.M.

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 750-तीन / 14

जिला -छत्तरपुर

प्रकारण क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारण क्रमांक
१४.८.१६	<p>यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक २६/अ-१९/२००५-०६ निगरानी में पारित आदेश दिनांक ८.१.२०१४ के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५० के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२- प्रकरण का सारांश यह है कि नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर ने प्रकरण क्रमांक ५७/अ-१९/१९९७-९८ में पारित आदेश दिनांक २८.८.९८ से ग्राम सॉदनी के ६४ व्यक्तियों को भूमि बन्टन किया।</p> <p>इसी प्रकार तहसीलदार राजनगर ने प्रकरण क्रमांक ३०/अ-१९/२००१-०२ में पारित आदेश दिनांक ११.७.२००२ से ग्राम सॉदनी के १५ व्यक्तियों को भूमि का बन्टन किया गया।</p> <p>उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पारित आदेशों के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील क्रमांक १९/२००४-०५ अपील क्रमांक २९/२००४-०५ तथा अपील क्रमांक ३०/२००४-०५ प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी रायजनगर ने संयुक्त आदेश दिनांक २१.</p>	३०/अ-१९/२००५-०६

BPSL

(M)

9.05 से बेरुम्याद मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी क्रमांक 26/अ-१९/२००५-०६ प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर ने आदेश दिनांक 8.

1.14 से निगरानी अंशतः स्वीकार की तथा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश दिनांक 21.9.05 निरस्त करते हुये भैयालाल, चिनुआ, जानकीबाई, पूरन, कन्हैयालाल के हित में दिये गये पट्टे निरस्त कर दिये तथा नायब तहसीलदार बसारी का आदेश दिनांक 11.7.2002 एवं प्रकरण क्रमांक 57/अ-१९/९७-९८ में पारित आदेश दिनांक 28.8.98 भी निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक की ओर से श्री आर० एस० सेंगर अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक 1 से 7 की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अधीनस्थ व्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4- उभयपक्ष के अधिवक्तागणों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 26/अ-१९/२००५-०६ निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8.1.14 के अवलोकन पर रियति यह है कि आयुक्त द्वारा आदेश के पद-२ में विवेचना की है कि:-

B
R
M

तहसीलदार राजनगर के यहां ग्राम सांदनी के अभिलेख में पेज 13 पर वर्ष 1958-59 खरौनी जमाबन्दी में मोनेजू, दरयावसिंह, रंजोर सींग, कन्हैयाजू का नाम मालकाना कास्तकार के रूप में दर्ज हैं जो अभिलेख में किस्त बंदी वर्ष 1975-76 तक आनावेदक के पिता जुझार सींग का नाम दर्ज है। उक्त किस्त बंदी खरौनी की नकल पेज 15 पर संलग्न हैं नायब तहसीलदार बसारी ने उक्त भूमियों का बन्टन प्र०क० 30/अ-19/2001-02 में आदेश दिनांक 11.7.2002 में अनावेदक क्रमांक-3 जानकीबाई एवं पूरनलाल को खसरा नबंर 6/2 में भूमि आबंटन की गई। इसी प्रकार नायब तहसीलदार ने खसरा नबंर 6/1 में अनावेदक क्रमांक-1 भैयालाल को भूमि बंटन में दी गई। अनावेदक क्रमांक-1, 3, 4 के पास पूर्व से एवं अनावेदक क्रमांक-5, 6 परिवार में भूमि होने के उपरांत भी नायब तहसीलदार द्वारा भूमि का बंटन किया गयां बंटन के समय न तो इस्तहार का प्रकाशन किया गया, दिनांक 6.2.85 को प्रकरण क्रमांक 472/अ-63/75-76 में शासकीय भूमि घोषित की गई जो अभिलेख में 1953 से किस्त खरौनी की नकलें लगी हैं उनकी सत्य प्रतिलिपि कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रमाणित है जो अभिलेख में अनुचिभागीय अधिकारी के अभिलेख में संलग्न है यह सभी नकलें 1956-57 खसरा पांचसाला 56-57 खसरा पांचसाला संबत् 2020, 2021, 2022, 2023, 2026 से 2030 एवं वर्ष 1974 से लेकर 1992-93 तक अनावेदकगण के पूर्वजों के नाम अभिलेख में दर्ज हैं। वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के कैफियत के कॉलम में उक्त भूमि म0प्र० शासन प्रकरण क्रमांक 472/अ-63/1975-76 में पारित आदेश दिनांक 6.2.1985 द्वारा भूमि म0प्र० शासन की गई है एवं बंटन में आवेदक को बंटित कर दी गई। बंटन अधिकारी

प्र
रा

(M)

ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 4 (3) में बंटन से संबंधित जो नियम वर्णित किये गये हैं उन नियमों का पालन नहीं किया । स्थल निरीक्षण नहीं किया गया ।

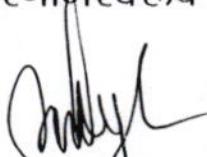
अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों एवं आदेशों के परीक्षण उपरांत उपरोक्तानुसार की गई विवेचना से स्पष्ट हे कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने न्यायदान के उद्देश्यों के विरीत जागर प्रस्तुत अपील्स बेलम्याद मानकर निरस्त करने में भूल की है तथा नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ-19/97-98 में पारित आदेश दिनांक 28.8.98 से ग्राम सॉदनी के 64 व्यक्तियों को किया गया भूमि बंटन एवं तहसीलदार राजनगर द्वारा ग्राम सॉदनी के 15 व्यक्तियों को प्रकरण कमांक 30/अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2002 से किया गया भूमि बन्टन नियम एवं प्रक्रिया के विरुद्ध पाया गया है जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का परीक्षण कर ऐसे बन्टन को निरस्त करने में तथा अधीनस्थ न्यायालयों के त्रुटिपूर्ण आदेशों को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, परन्तु विद्वान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी कर दी कि ग्राम सांदनी के अभिलेख में पेज 13 पर वर्ष 1958-1959 खतौनी जमाबन्दी में मोनेजू, दरयाव सिंह, रंजोर सींग, कन्हैयाजू का नाम

RJL

(M)

मालकाना कार्यकार के रूप में दर्ज हैं जो अभिलेख में किस्त बंदी वर्ष 1975-76 तक आनावेदक के पिता जुझार सींग का नाम दर्ज है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ-19/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8.1.2014 भूमि बन्टन निरस्त करने तक उचित होने से यथावत रखते भूमि म0प्र0 शासन की दर्ज करने एवं कब्जा हटाने के निर्देश देने वाले भाग को संशोधित किया जाता है तथा भूमि पूर्ववत खसरा सन् 1958-59 लगायत किस्तबंदी 1975-76 अनुसार अंकित भूमिस्वामियों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं यदि उक्त वर्षों के अभिलिखित भूमिस्वामी जीवित नहीं हैं तब उनके विधिक वारिसानों के नाम भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज की जाय। परिणामस्वरूप निगरानी निरस्त की जाती है।


(एम० कौ सिंह)
सदस्य

R
१५८